एक नजर

उत्तराखंड में 'प्ली बार्गेनिंग' प्रावधानों के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश

स्वतंत्र चेतना

देहरादून। शासन के संयुक्त सचिव गजेन्द्र सिंह कफलिया ने प्रदेश के संबंधित विभागों को पत्र प्रेषित कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत 'प्ली बार्गेनिंग' के प्रावधानों के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि न्याय प्रणाली को अधिक सुगम, त्वरित और प्रभावी बनाने और अदालतों में लंबित मुकदमों के बोझ को कम करने के उद्देश्य से इस व्यवस्था को लागू किया गया है। इसलिए जनहित में इसके प्रावधानों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जानी आवश्यक है। इस संबंध में पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग, अपर सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग, निदेशक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, अपर निदेशक अभियोजन निदेशालय तथा संयुक्त निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तराखण्ड को भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पत्र में कहा गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत किए गए नए प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाना और अदालतों पर लंबित मामलों के दबाव को कम करना है। इसके तहत सात वर्ष से कम कारावास की सजा वाले मामलों में आरोप तय होने के 30 दिनों के भीतर आरोपी को प्ली बार्गेनिंग के लिए आवेदन करने का वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है।

बालमणा में गुलदार की दहशत बरकरार

स्वतंत्र चेतना

पौड़ी गढ़वाल। गढ़वाल वन प्रभाग की पौड़ी रेंज के बालमणा गांव में काम कर घर वापस लौट रहे एक राज मिस्त्री को गुलदार द्वारा निवाला बनाए जाने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश बना हुआ है। घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत भी बनी हुई है। गुलदार की दहशत के चलते ग्रामीणों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। वहीं, घटना के बाद वन विभाग की टीम ने यहां डेरा डाल दिया है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग के प्रति रोष भी जाहिर किया था। और मोके पर पहुंचे आला अफसरों का घेराव कर गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की थी। हमले के बाद यहा विभागीय शूटर भी तैनात किए गए हैं। गुलदार की लोकेशन के लिए यहां ट्रेप केमेरे भी लगाए गए हैं। डीएफओ गढ़वाल महातिम यादव ने बताया कि क्षेत्र में टीम तैनात की गई है। गुलदार को कैद करने के लिए पिंजरे भी लगाए गए है। वहीं, कांग्रेस नेता सुंदरलाल मुयाल ने पीड़ित परिवार के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए कहा कि परिवार की उनके द्वारा हरसंभव मदद की जाएगी। उन्होंने सरकार से जंगली जानवरों के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की।

जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल की सर्किट बेंच स्थापित करने के मामले में हुई सुनवाई

स्वतंत्र चेतना

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल में जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल की सर्किट बेंच स्थापित करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को इस संबंध में आवश्यक निर्णय लेने की बात कही। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हल्द्वानी टैक्स बार एसोसिएशन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि नैनीताल में जीएसटी ट्रिब्यूनल की सर्किट बेंच स्थापित की जाए। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से न्यायालय को 2 मई 2025 का एक पत्र सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि हाई कोर्ट मुख्यालय नैनीताल में जीएसटी ट्रिब्यूनल की सर्किट बेंच स्थापित करने का अंतिम निर्णय राज्य सरकार को लेना है। राज्य सरकार की ओर से अदालत से समय की मांग करते हुए कहा गया कि उन्हें यह पता लगाने के लिए समय चाहिए कि नैनीताल में सर्किट बेंच की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार की मांग को स्वीकार करते हुए दो सप्ताह का समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए मार्च माह की तिथि नियत की है।

लिवाइज के 'बिहाइंड एवरी ओरिजिनल' अभियान की आलिया भट्ट के साथ नई शुरूआत

स्वतंत्र चेतना

देहरादून। पिछले 150 से अधिक वर्षों से, लिवाइज उन लोगों की पहली पसंद रहा है जो संस्कृति को नई दिशा देते रहे हैं। संगीत और खेल से लेकर फैशन और कला तक, लिवाइज जींस हर उस महत्वपूर्ण मोड़ की गवाह रही है जहाँ बदलाव की शुरूआत हुई। इसे वे लोग पहनते हैं जो न केवल प्रगति की राह पर चलते हैं, बल्कि आने वाले कल की दिशा भी तय करते हैं। 'बिहाइंड एवरी ओरिजिनल' अभियान इसी महान विरासत को आगे बढ़ाता है। यह वैश्विक स्तर पर मौलिकता के पीछे की गहरी सोच का जश्न मनाता है—वह जिज्ञासा, अटूट विश्वास और दुनिया को एक अलग नजरिये से देखने का साहस, जो असल प्रगति को जन्म देते हैं। इस अभियान का मुख्य केंद्र अभिनेत्री आलिया भट्ट हैं, जो एक ऐसी कलाकार और वैश्विक सांस्कृतिक आइकन हैं। अपनी प्रेरणा साझा करते हुए आलिया कहती हैं, मैं हमेशा से ही जिज्ञासु रही हूँ और हर चीज के पीछे क्या से ज्यादा क्यों को समझना चाहती हूँ। ऑरिजिनल होना थोड़ा उलझा हुआ और अधूरा (इम्पर्फेक्ट) हो सकता है, लेकिन वह पूरी तरह से आपका अपना होता है।

पेट्रो पदार्थों एवं रसाई गैस कीमतों पर केंद्र का भरोसा स्वागत्योग्यः भाजपा

स्वतंत्र चेतना

देहरादून। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम एशिया में युद्ध के चलते पेट्रो पदार्थों एवं रसोई गैस की कीमतों पर केंद्र सरकार के भरोसे का स्वागत किया है। गंभीर विश्व संकट में भी किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, देश में पेट्रोलियम उत्पादों का प्रयाप्त स्टॉक है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने गुरुवार को एक बयान जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर सरकार ने पहले से सभी आवश्यक तैयारी की हुई है, आगे जो भी कड़े कदम उठाने पड़े, उन पर संगठन और जनता मोदी के साथ मजबूती से खड़े हैं। पेट्रोलियम पदार्थों की कमी और कीमत को लेकर उठाई जा रही चिंता पर पार्टी का रुख स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि जनता को मोदी सरकार पर पूरा भरोसा है और मजबूती के साथ उनके प्रत्येक कदम के साथ खड़ी है। भट्ट ने केंद्र सरकार के पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत वृद्धि न करने के भरोसे पर संतुष्टि व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि किसी को तेल, गैस की कमी या कीमत वृद्धि को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम एकमात्र देश हैं, जहां खाड़ी की आपातकाल परिस्थितियों के बाद भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। खाड़ी क्षेत्र में जारी युद्ध के कारण पेट्रोलियम पदार्थों और रसोई गैस आपूर्ति को लेकर सरकार गंभीर है। वर्तमान वैश्विक संकट एक ऐसी असाधारण परिस्थिति है, जिसने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। भाजपा का मानना है कि इस कठिन समय में राष्ट्रहित सर्वोपरि है। पार्टी इस संकट से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे आवश्यक और कड़े कदमों का पूर्ण समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा और देश की जनता, वैश्विक संकट और राष्ट्रीय हित में केंद्र सरकार के साथ खड़ी है। निसंदेह खाड़ी युद्ध के कारण कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित हुई है और अंतरराष्ट्रीय कीमतों में भारी उछाल आया है। यह संकट हमारे नियंत्रण से बाहर है, परंतु सरकार ने जिस तत्परता से वैकल्पिक स्रोतों से तेल की व्यवस्था की है, वह प्रशंसनीय है। भाजपा को उम्मीद है कि केंद्र एवं सभी राज्य सरकारें गैस और डीजल की किल्लत का फायदा उठाने वाले जमाखोरों और कालाबाजारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगी, ताकि आम जनता को कम से कम असुविधा हो। उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन और सरकार इस संकट की घड़ी में देश की जनता के साथ खड़े हैं। हमें विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और जनता के धैर्य से हम इस ऊर्जा संकट का सफलतापूर्वक सामना कर बाहर निकल आएंगे।

विधानसभा में चारधाम यात्रा, साइबर ठगी और कॉलेज नामकरण पर हुई चर्चा

चारधाम यात्रा से बढ़ रही राज्य की आर्थिकी, सरकार ने बेहतर सुविधाओं का दिया भरोसा, भीमराव अम्बेडकर के नाम पर कॉलेज बनाने पर सरकार ने कहा- एक नहीं दो डिग्री कॉलेज

स्वतंत्र चेतना

भराड़ीसैंण। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन गुरुवार को सदन में चारधाम यात्रा की व्यवस्था और तैयारियों के अलावा महाविद्यालयों के नाम बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर के नाम पर नामकरण को लेकर सदन में चर्चा हुई। सरकार ने कहा कि अंबेडकर के नाम पर कॉलेज के नाम रखने से कोई परहेज नहीं है, बल्कि एक नहीं दो डिग्री कॉलेज उनके नाम पर बनाए जाएंगे।

सदन में सदस्य विक्रम सिंह नेगी और लखपत बुटोला ने नियम 58 के तहत चारधाम यात्रा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह उत्तराखंड की आस्था और आर्थिकी दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सुझाव दिया कि यात्रा के दौरान ऑनलाइन और ऑफलाइन व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाए और अनुभवी लोगों को यात्रा प्रबंधन में तैनात किया जाए। साथ ही कूड़ा उठान की बेहतर व्यवस्था और यात्रा के दौरान होटल बुकिंग, हवाई टिकट सहित अन्य आवश्यक कार्यों में ठगी पर विशेष ध्यान देने की भी मांग की।

लखपत बुटोला ने कहा कि चारधाम क्षेत्र के विधायकों को यात्रा से संबंधित बैठकों में नहीं बुलाया जाता, जबकि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भागीदारी जरूरी है। इस पर मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सरकार चारधाम यात्रा को लेकर गंभीर है और इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2001 में करीब 10 लाख, 2015 में लगभग 8 लाख, 2022 में 46 लाख और 2025 में 51 लाख से अधिक श्रद्धालु यात्रा पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि सभी यात्री चारों धाम नहीं जाते, इसलिए यात्रियों की संख्या एक बराबर नहीं हो सकती। मंत्री ने बताया कि बदरीनाथ और केदारनाथ सहित चारधाम मार्गों पर तय स्थानों पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए चेकिंग की जाती है। राज्य सरकार का उद्देश्य यात्रियों को ञअतिथि देवो भवःञ की भावना के अनुरूप बेहतर सुविधाएं देना है, क्योंकि यह राज्य की आर्थिकी को भी मजबूत करते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए टोल-फ्री नंबर जारी किया गया है और 31 मार्च तक यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। सरकार सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ ने कहा कि प्रदेश में 128 महाविद्यालयों का नाम परिवर्तन किया गया, लेकिन किसी भी महाविद्यालय का नाम भीमराव अम्बेडकर के नाम पर नहीं रखा गया। उन्होंने इस संबंध में सरकार और विभाग को पत्र भी भेजा है। इस पर मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि किच्छा डिग्री कॉलेज भाजपा सरकार के समय बनाया गया था और इस मामले में जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है। महापुरुषों के नाम पर संस्थानों का नाम रखने के लिए जनपद स्तरीय समिति का गठन किया गया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी भीमराब अम्बेडकर के नाम पर महाविद्यालय का नाम रखने की मांग की। इसमे सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जिस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि समिति की रिपोर्ट के आधार पर नाम तय किया जाएगा। मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार को बाबा साहब के नाम पर महाविद्यालय रखने में कोई परहेज नहीं है और एक नहीं बल्कि दो डिग्री कॉलेज भी उनके नाम पर बनाए जाएंगे।

घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर एक्शन ले सरकारः कांग्रेस

बजट सत्र के चौथे दिन सदन में गूंजा गैस की किल्लत का मामला

स्वतंत्र चेतना

भराड़ीसैंण। प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण विधानसभा में चल रहे बजट सत्र 2026 के चौथे दिन गुरुवार को घरेलू गैस सिलेंडरों की किल्लत और कालाबाजारी का मुद्दा उठा। विपक्ष ने सरकार से रसोई गैस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की।

सदन में कांग्रेस नेता व प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने नियम 58 के तहत मुद्दा उठाते हुए कहा कि प्रदेश में 359 गैस एजेंसियां संचालित हो रही हैं, जहां करीब 29 लाख घरेलू और लगभग 55 हजार व्यावसायिक गैस कनेक्शन हैं। उन्होंने बताया कि केवल देहरादून में ही लगभग 70 हजार घरेलू और 19 हजार व्यावसायिक कनेक्शन हैं। आज उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर ऑनलाइन बुकिंग बंद हो गई है और गोदामों पर लंबी कतारें लग रही हैं। उपभोक्ताओं को बुकिंग के 25 दिन बाद सिलेंडर मिल रहे हैं। व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति भी प्रभावित होने से होटल, ढाबों और हॉस्टलों में रहने वाले छात्रों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जैसी वैश्विक परिस्थितियों के कारण गैस आपूर्ति प्रभावित हुई है। उन्होंने बताया कि कालाबाजारी रोकने के लिए राज्य सरकार ने अभियान तेज कर दिया है। मुख्य सचिव ओ सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं और कालाबाजारी करने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि नैनीताल में इस संबंध में तीन एफआईआर दर्ज की गई हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति प्रभावित होने के बावजूद हॉस्टलों में रहने वाले छात्रों को घरेलू गैस सिलेंडर उपयोग करने की छूट दी गई है, जिससे उन्हें परेशानी नहीं होगी। सदन की पीठ ने नियम 58 के तहत दिए गए नोटिस को अग्राह्य करते हुए सरकार को निर्देश दिया कि प्रदेश में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर कड़ी निगरानी रखी जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं के लिए 44.64 करोड की दी वित्तीय स्वीकृति

स्वतंत्र चेतना

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के तहत जन सुविधाओं के विकास, आपदा न्यूनीकरण के प्रयासों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अवस्थापना सुविधाओं के विकास के साथ पार्किंग, सामुदायिक भवनों के निर्माण, विकासखंड स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास आदि के लिए 44.64 करोड़ की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति दे दी है।

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मिटीगेशन प्रोग्राम (एनएलआरएमपी) विषयक कार्यशाला में एनडीएमए द्वारा सम्भावित जोखिम संवेदनशील भू-स्खलन क्षेत्रों के न्यूनीकरण के लिए प्रथम किश्त के रूप में 1.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन दिया है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों के राजकीय औद्योगिक आस्थानों की मरम्मत, सुदृढीकरण कार्य के लिए एमएसएमई अवस्थापना विकास मद के अन्तर्गत कुल धनराशि 1.99 करोड़ रुपये, राजकीय जनजाति छात्रावास खटीमा, ऊधम सिंह नगर में विभिन्न (02) मरम्मत एवं निर्माण कार्यों के लिए 46.14 लाख रुपये एवं राजकीय जनजाति छात्रावास काशीपुर, ऊधम सिंह नगर में विभिन्न (02) मरम्मत एवं निर्माण कार्य के लिए 37.71 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन किया है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर के अन्तर्गत गोखार्सध धर्मशाला, चन्द्रबनी के जीर्णोद्धार एवं पार्किंग का निर्माण किये जाने के लिए 38.97 लाख, जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र मसूरी के गुनियाल गांव सामुदायिक भवन का जीर्णोद्धार व सौन्दर्यीकरण किये जाने के लिए 65.93 लाख के साथ ही जिला कारागार, सितारगंज के विस्तारीकरण संबंधी कार्य के लिए 38.15 करोड की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन किया है। मुख्यमंत्री ने 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में स्थानीय शासनों के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संस्तुति अनुदान के अन्तर्गत ब्लॉक स्तर पर लोक स्वास्थ्य इकाइयों की वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुमोदित कार्ययोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 मे 1.62 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुमोदन किया है।

मुख्यमंत्री ने राज्य में खाद्य व रसद व्यवस्था की सतत निगरानी के लिए अधिकारियों की विशेष तैनाती

स्वतंत्र चेतना

देहरादून। वैश्विक परिदृश्य में उत्पन्न वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने खाद्य एवं रसद आपूर्ति की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखण्ड राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र में विभिन्न अधिकारियों एवं विशेषज्ञों की तैनाती की गई है। यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गई और अग्रिम आदेशों तक रहेगी। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार इन अधिकारियों और विशेषज्ञों की तैनाती का उद्देश्य प्रदेश में खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, आपूर्ति व्यवस्था तथा वितरण प्रणाली की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही खाद्य एवं रसद से संबंधित सूचनाओं का नियमित संकलन, उनका विश्लेषण तथा विभिन्न विभागों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। निर्धारित रोस्टर के अनुसार तैनात अधिकारी एवं विशेषज्ञ उत्तराखण्ड राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र में नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे। वे प्रतिदिन खाद्य एवं रसद की स्थिति की समीक्षा करेंगे, आवश्यक सूचनाओं का संकलन एवं विश्लेषण करेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी परिस्थिति में खाद्यान्न, एलपीजी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित नहीं होनी चाहिए तथा स्थिति पर निरंतर निगरानी रखी जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदेश में खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर्याप्त है और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार सभी व्यवस्थाओं पर लगातार नजर बनाए हुए है ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो। राज्य सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से प्रदेश में खाद्य एवं रसद आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी तथा किसी भी संभावित आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने में सहूलियत मिलेगी।

सूचना

मैंने अपना नाम रंजू सैनी से बदलकर रंजीता सैनी रख लिया है। अब मुझे भविष्य में रंजीता सैनी के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाये।

रंजीता सैनी पत्नी श्री सुनील सैनी
निवासी-मकान नम्बर-170,
ज्ञानलोक कॉलोनी, कनखल
तहसील व जिला हरिद्वार।

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में घोटाले के कांग्रेस के आरोपों की सीएजी रिपोर्ट में हुई पुष्टिः धस्माना

स्वतंत्र चेतना

देहरादून। कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि लगभग छह सात वर्षों तक पूरे देहरादून महानगर को खोद डाला गया और लगभग बाईस तरह से शहर को स्मार्ट बनाने की लंबी चौड़ी जुमलेबाजी की गई, लेकिन सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च करने के बाद जब इस योजना के पूर्ण होने की घोषणा की गई तो स्मार्ट कि जगह शहर और बदतर हाल में हो गया और तभी हमने इस पूरी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कार्यों की गुणवत्ता और घोटाले की बात कही थी, जिस पर अब सीएजी रिपोर्ट ने भी मोहर लगा दी है।

कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना गुरुवार को यहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

दरअसल, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत २०१७ में तीसरे फेस में देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना केंद्र सरकार ने स्वीकृत की थी, जिसे वर्ष २०२३ तक पूरा किया जाना था किंतु समय पर कार्य ना होने से इसके समय में विस्तार दिया जाता रहा। २०२५ में आधे अधूरे निम्न स्तरीय कार्य के बावजूद इसके पूर्ण होने की घोषणा तत्कालीन सीईओ ने कर दी। इस पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता धस्माना ने कहा कि इस योजना के तहत कार्य आवंटन में अनियमितताएं, कार्यों की गुणवत्ता व कार्यों को आधा अधूरा छोड़ना जैसे मामले प्रकाश में आने के बावजूद कोई जांच व कोई कार्यवाही कार्यदाई संस्थाओं के खिलाफ नहीं हुई, क्योंकि इस घोटाले को पूरी तरह से राज्य सरकार के संरक्षण में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधिकारियों ने इस प्रोजेक्ट के अध्यक्ष की देखरेख में किया। धस्माना ने कहा कि इस योजना के तहत भूमिगत विद्युतीकरण के कार्य, ट्रैफिक सिस्टम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्कूलों व महाविद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे व वाईफाई, स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट शौचालय आदि कार्यों पर सैकड़ों करोड़ खर्च किए गए लेकिन कार्य या तो हुए नहीं या केवल दिखावे के लिए निम्न स्तर के कार्य हुए। धस्माना ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के समय अनेक बार कांग्रेस द्वारा यह मुद्दे उठाए गए किंतु सरकार गूंगी बहरी बनी रही और घोटाले होते रहे। श्री धस्माना ने कहा कि अगर इस पूरे प्रोजेक्ट की उच्च स्तरीय जांच सीबीआई से करवाई जाए तो भाजपा सरकार का यह सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा।

उत्तर रेलवे

निविदा सूचना

पत्रांक : 75-W/2/3/WA/Publication दिनांक : 11.03.2026

भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रवर मण्डल अभियन्ता / मुख्यालय / मुरादाबाद द्वारा ई टेन्डर निम्न टेन्डर संख्या के अर्न्तगत आमंत्रित किये जाते है। धरोहर राशि का भुगतान निविदादाता द्वारा केवल IREPS पोर्टल पर उपलब्ध नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से आनलाइन भुगतान करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर चैक, डिपाजित रसीद आदि स्वीकार्य नहीं होंगे। टेन्डर से संबधित अन्य जानकारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर देखें।

Tender No. Date	318-DRM-MB-25-26 dt. 11.03.2026	325-DRM-MB-25-26 dt. 11.03.2026
Name of work	Renewal of 63 Nos Turnouts(3 No(s) 1 in 12 FS+CS+CMSC; 7 Nos 1 in 12 CS+CMSC; 31 Nos 1 in 8.5 CS+ CMSC; 01 No Diamond Xing single slip and 21 nos Trap)and other associated works and Deep screening work, removal of muck and other associated works in connection with Improvement of MB, CH, SSKA, MCV, KD, RJK, JRJ, GTF, SHTS, AFR, DUB, KEG, AO, BJ, DN, BTG, RGB, AUR yards under Sr. DEN/HQ/MB.	Improvement of Water supply arrangement at Chandausi, Raja Ka Sahaspur, Babrala, Rajghat Aonla.
Tender Closing Date Time	07.04.2026	07.04.2026
Advertised Value (Rs.)	3,43,62,020.62/-	2,81,83,854.76
Earnest Money (Rs.)	3,21,800.00	2,90,900.00
Tender Cost (Rs.)	00	00
Bidding Start Date	24.03.2026	24.03.2026
Period of Completion	06 Month	06 Month

829/26

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

एलपीजी और ईंधन की कालाबाजारी पर सख्त निगरानी, तीन दिन में 280 निरीक्षण, 74 गैस सिलेंडर जब्त

स्वतंत्र चेतना

देहरादून। उत्तराखंड में एलपीजी और ईंधन की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने प्रदेशभर में व्यापक जांच अभियान चलाया है। तीन दिन में विभिन्न जनपदों में 280 निरीक्षण और अवैध भंडारण और दुरुपयोग के मामलों में 74 गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के आयुक्त ने बताया कि 10, 11 और 12 मार्च तक विभिन्न जनपदों में निरीक्षण और अभियान के तहत कुल 280 निरीक्षण किए गए। जांच के दौरान 58 स्थानों पर छापेमारी की गई, जबकि चार मामलों में एफआईआर दर्ज कराई गई है। उन्होंने बताया कि अवैध भंडारण और दुरुपयोग के मामलों में 74 गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। इसके अलावा कार्रवाई के दौरान एक काटा (वजन माप उपकरण) और दो रिफिलिंग किट भी जब्त की गई हैं। विभाग की ओर से अनियमितताओं पर 4600 रुपये का अर्थदंड भी वसूला गया है। राज्य सरकार उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गैस और ईंधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार की कालाबाजारी, जमाखोरी या अवैध रिफिलिंग को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि यदि कहीं भी एलपीजी या ईंधन से संबंधित अनियमितता, कालाबाजारी या अवैध रिफिलिंग की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों को दें, ताकि त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। विभाग की ओर से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए आगे भी इसी प्रकार सघन जांच अभियान जारी रखा जाएगा।

GRIHUM HOUSING FINANCE Apna Ghar, Apni Pehchan

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
रजिस्टर्ड ऑफिसः 6वीं मंजिल, बी बिल्डिंग, गागा ट्रूनो, लोहेगांव, पुणे, महाराष्ट्र 411014
यूनिट से ब्रांचः आर.के. टावर, दूसरी मंज़िल, स्वामी हरिचूराम ट्रस्ट के सामने, कनखल रोड, आर्य नगर चौक, ज्वालापुर, हरिद्वार, उत्तराखंड - 249407

ई-नीलामी बिक्री सूचना
सुरक्षित अचल संपत्ति की बिक्री
सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति की बिक्री

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना। आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटर को सूचित किया जाता है कि गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे अधिनियम के अनुसार "सुरक्षित लेनदार" कहा गया है) के पास बंधक रखी गई नीचे वर्णित अचल संपत्तियों का कब्जा सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसरण में ले लिया गया है।

सुरक्षित संपत्तियों की बिक्री 13-04-2026 को ई-नीलामी के माध्यम से "जैसी है वैसी", "जो भी है" और "जो भी मौजूद है" के आधार पर की जाएगी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइट https://www.bankeauctions.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी आयोजित करने जा रहे हैं। बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया GHFL/सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट www.grihumhousing.com पर दिए गए लिंक को देखें।

प्रस्ताव संख्या ग्राहक का नाम {ए}	मांग सूचना दिनांक और उत्कृष्ट राशि {बी}	कब्जे की प्रकृति {सी}	विवरण संपत्ति का {डी}	संरक्षित कीमत {ई}	ईएमडी (10% आरपी के) {एफ}	ईएमडी जमा करने की तिथि {जी}	वृद्धिशील बोली {एच}	संपत्ति निरीक्षण दिनांक एवं समय {क}	दिनांक और का समय नीलामी {जे}	ज्ञात अतिक्रमण-प्रतिबंध/अदालत मामले यदि कोई हों {के}
ऋण संख्या HF0173H21100125 सतीश कुमार सिंह (ऋणकर्ता) सुनीता सिंह (सह-ऋणकर्ता) राजेश्वर सिंह	नोटिस दिनांक: 08-08-2025 कुल देय राशि: 1779515/- रुपये (सत्रह लाख उन्यासी हजार पांच सौ पंद्रह रुपये मात्र) जो 08-08-2025 तक देय है, साथ ही वसूली तक 12.75% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी देय है।	भौतिक	प्लॉट संख्या A-3 का वह आवासीय मकान, जिसका माप पूर्व में 16.5 फीट, पश्चिम में 16.5 फीट, उत्तर में 33 फीट और दक्षिण में 33 फीट है, कुल क्षेत्रफल 544.5 वर्ग फीट (यानी 50.60 वर्ग मीटर) है। इसमें दो कमरे, रसोईघर, शौचालय, स्नानघर और 50.60 वर्ग मीटर का ढका हुआ सीढ़ियाँ हैं। खसरा संख्या 534/2 के अंतर्गत, यह संपत्ति राजा गार्डन, गांव जगजीतपुर मुस्तकाम (नगरपालिका सीमा के भीतर), परगना, तहसील ज्वालापुर, जिला हरिद्वार में स्थित है। इसकी सीमाएँ पूर्व में 12 फीट चौड़े मार्ग से, उत्तर में प्लॉट संख्या A-3 के शेष भाग से, पश्चिम में पवन (अन्य) के मकान से और दक्षिण में राजपाल सिंह के प्लॉट संख्या A-4 से लगती हैं। कुल क्षेत्रफल 544.5 वर्ग फीट है।	2049469/- रुपये (बीस लाख उनचास हजार चार सौ उनहत्तर रुपये केवल)	204946.90 रुपये/- (दो लाख रुपये चार हजार नौ सौ छियालीस रुपये और नब्बे पैसे मात्र)	10-04-2026 शाम 5 बजे से पहले	10,000/-	06-04-2026 (सुबह 11 बजे शाम 4 बजे)	13-04-2026 (सुबह 11 बजे दोपहर 2 बजे)	शून्य

इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित लेनदार शाखा और नीलामी वाली संपत्तियों का दौरा करें, स्वयं पूछताछ करें और अतिरिक्त शुल्कों, भारों और किसी भी तृतीय-पक्ष हितों का पता लगाएं और बोली जमा करने से पहले सभी पहलुओं से स्वयं को संतुष्ट कर लें। संपत्ति कर, बिजली/पानी के बिल और संपत्ति से जुड़े किसी भी अन्य बकाया जैसे सभी वैधानिक देय राशियों का पता लगाकर सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान किया जाना आवश्यक है। इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा और नीलामी सेवा प्रदाता (सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) से लॉगिन आईडी और पासवर्ड पहले से प्राप्त करना होगा, जो ई-बोली के लिए अनिवार्य है।

पता- प्लॉट नंबर-68, तीसरी मंजिल, गुड़गांव, हरियाणा-122003। हेल्पलाइन नंबर- 7291981124, 25, 26। ईमेल आईडीः Support@bankeauctions.com। संपर्क व्यक्तिः विनोद चौहान, ईमेल आईडीः delhi@c1india.com, संपर्क नंबरः 9813887931। कृपया ध्यान दें कि इच्छुक बोलीदाता केवल इन्हीं से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक खरीदार/बोलीदाता को बयाना राशि (ईएमडी) एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी के माध्यम से "गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड - नीलामी आय खाता" में जमा करनी होगी। बैंकः आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। खाता संख्या- 091551000028 और IFSC कोड- ICIC0000915, ICICI बैंक लिमिटेड, पंचशील टेक पार्क, गणपति चौक के पास, 43/44 विमान नगर 411014, किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक पर 10-04-2026 को या उससे पहले आहरित होना चाहिए और https://www.bankeauctions.com पर अपना नाम पंजीकृत करें और निशुल्क यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करें तथा सेवा प्रदाता से ई-नीलामी का प्रशिक्षण प्राप्त करें। वेबसाइट पर पंजीकरण के बाद, इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करनी होंगी, ईमेल करनी होंगी और स्व-सत्यापित हार्ड कॉपी निम्नलिखित पते पर भेजनी होंगीः आर.के. टावर, दूसरी मंजिल, स्वामी हरिचुरम ट्रस्ट के सामने, कंखल रोड, आर्य नगर चौक, ज्वालापुर, हरिद्वार, उत्तराखंड - 249407। मोबाइल नंबर। +91 8281138143 ईमेल आईडी p.adith@grihumhousing.com नियमों और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया https://www.bankeauctions.com & www.grihumhousing.com पर जाएं और ई-नीलामी में भाग लें। यह सूचना सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम-2002 के नियम 8(6) के तहत उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/बंधक/गारंटर को 30 दिनों की सूचना भी मानी जानी चाहिए।

दिनांकः 13.03.2026 स्थानः- हरिद्वार, उत्तराखंड

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी